



Aug. 60 Sept.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 1 अगस्त, 1998/10 भाद्रपद, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

यतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः* हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त* प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देती है।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

*गांव पस्ता, तहसील सदर, जिला मण्डी में पेड़ी-पस्ता पुल के निर्माण हेतु।

संख्या पी0 बी0 डब्ल्यू0 (बी0)ए0(7) 1-106/98.

शिमला-2, 20 जुलाई, 1998.

विस्तृत विवरणी

जिला : मण्डी

तहसील : सदर

गांव 1	खसरा नं0 2	क्षेत्र (बीघों में)		
		3	4	5
पस्ता/119	253/1	0	1	5
	254/1	0	3	15
किता ..	2	0	5	0

*गांव वैहल, तहसील सदर, जिला मण्डी में तलवाड़-पैड़ी-रती सड़क के निर्माण हेतु।

संख्या पी0 बी0 डब्ल्यू0 (बी) ए (7) 1-108/98.

शिमला-2, 21 जुलाई, 1998.

वैहल/111	281/1	0	5	7
	267/1	1	12	16
किता ..	2	1	18	3

शुद्धिपत्र

शिमला-2, 20 जुलाई, 1998

संख्या पी0 बी0 डब्ल्यू0 (बी)ए0(7) 1-90/97.— इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6-3-98 जो कि गांव घरवासड़ा, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी में भराड़ी-मढ़ी बाया गरली सड़क के निर्माण हेतु धारा 4 के अधीन जारी की गई है, में निम्नलिखित खसरा नम्बरों को भी पढ़ा जाए :—

विवरणी

जिला : मण्डी

तहसील : सरकाघाट

गांव 1	खसरा नं0 2	क्षेत्र (हैक्टेयरों में)		
		3	4	5
घरवासड़ा	56/1	0	00	25
	125/1	0	02	33

1	2	3	4	5
	124/1	0	00	64
	11/1/1	0	00	09
	11/1	0	00	27
	14/1	0	02	22
	13/1	0	00	40
	17/1	0	03	36
	21/1	0	04	83
	18/1	0	00	27
	23/1	0	02	00
	24/1	0	01	57
	26/1	0	00	70
	123/1	0	00	35
	183/1	0	00	55
	184/1	0	00	44
	185/1	0	03	86
	186/1	0	01	54
	192/1	0	00	13
	191 सा 0	0	06	70
	189/1	0	00	56
	190/1	0	00	30
	कित्ता ... 22	0	33	36

शिमला-2, 21 जुलाई, 1998

संख्या पी 0 बी 0 डब्ल्यू 0 (बी 0) ए 0 (7) 1-107/98.—यतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव धुसाड़ा अम्बल, तहसील अम्ब, जिला ऊना में नंगल-मुबारकपुर-तलवाड़ा सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देती है।

4. कोई भी हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक

निर्माण विभाग, हमीरपुर के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला : ऊना

तहसील : अम्ब

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र (हैक्टेयर)
धुसाड़ा अम्बल	761/1	0 00 46
	766/1	0 06 30
	767/1	0 05 22
	771/1	0 05 40
	799/1	0 07 32
कित्ता	5	0 24 70

शिमला-2, 24 जुलाई, 1998

संख्या लो० नि० (ख०) ए० (7) 1-227/97.—यतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बेहरड़ा, उप-तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर में गंगुवाल-टोवा सड़क (क्षीर गंगा पुल) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है। उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उप-धारा-4 के अधीन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (2) के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

विवरणी

जिला : बिलासपुर

तहसील : श्री नैना देवी जी

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बीघा बिस्वा
बेहरड़ा	320	8 03
	321	5 08
	372/331	4 18
	354/343	1 05
	344	0 01
कित्ता	5	19 15

शिमला-2, 24 जुलाई, 1998

संख्या पी0 बी0 डब्ल्यू0(बी0)ए0(7)1-21/97. —यतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः गांव पनोही, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर में पनोह-टकरेहड़ा-घुमारवीं सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह घोषित जाता है कि नीचेविवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विटर फील्ड, शिमला-3 को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विटर फील्ड, शिमला-3 के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : बिलासपुर

तहसील : घुमारवीं

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बीघा बिस्वा
पनोह	1/1	0 3
	323/306/1	0 7
किता ..	2	0 10

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

आवास विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 27 जुलाई, 1998

संख्या आवास-6(एफ0)6-8/92-लूज.—यतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि आवास बोर्ड हिमाचल प्रदेश, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 3 के खण्ड (सी0सी0) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः

गांव फाटी बनोगी, मौजा सारी, परगना लगसारी, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में आवास बस्ती के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अपेक्षित है। अतः एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्नलिखित विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, [उप मण्डल अधिकारी (नागरिक)] कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को एतद्वारा उक्त भूमि के अर्जन करने के लिए आदेश लेने का निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक समाहर्ता, भू-अर्जन कुल्लू (उप मण्डल अधिकारी नागरिक) कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला : कुल्लू

तहसील : कुल्लू

गांव	खसरा न०	रकबा (बीघों में)
फाटी बनोगी	3809	1 00
मौजा सारी	3810	1 18
परगना लगसारी	3813	0 10
	3815	0 19
	3799	2 00
	3807	1 15
	3808	0 06
	3811	0 03
	3812	0 04
	3814	1 00
कुल	10	9 3

शिमला-2, 27 जुलाई, 1998

संख्या आवास-6 (एफ0) 6-8/92.—यतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि आवास बोर्ड हिमाचल प्रदेश, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 3 (सी0सी0) के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः मौजा सारी, फाटी बनोगी, तहसील एवं जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में आवास बस्ती के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि का उपरोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और अधिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देती हैं।

4. कोई भी हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशन होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता (एस0 डी0 एम0), कुल्लू के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला : कुल्लू

तहसील : कुल्लू

गांव	खसरा नं०	रकबा (बीघों में)
फाटी बनोगी, मौजा सारी	3857	0 14 00
	3858	0 13 00
	3859	2 03 00
	3860	3 04 00
	4301/3862	0 13 12
	3803	2 17 00
	3884	2 01 00
	4259/3856	0 06 00
	4262/3896	0 10 00
कुल .. 9		13 01 12

शिमला-2, 27 जुलाई, 1998

संख्या आवास-6 (एफ0)7-1/92-II.—यतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि आवास बोर्ड हिमाचल प्रदेश, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 3 के खण्ड (सी0सी0) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः ग्राम नायली उपरली, मौजा मुच्छाली, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में आवास बस्ती के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्नलिखित विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन करना अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता (उप-मण्डलाधिकारी नागरिक), ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को एतद्वारा उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि का रखांक भू-अर्जन समाहर्ता, ऊना [उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) ऊना], जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : ऊना

तहसील : बंगाणा

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र (हेक्टेयरों में)
	201	0 04 85
	202	0 04 62
कित्ता ..	2	0 09 47

आदेश द्वारा,

एस० एस० परमार,
वित्तायुक्त एवं सचिव।